

द्वितीय अपील न. /2017

प्रस्तुती ता. 21 दिसम्बर 2017

श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल महोदय, के न्यायालय के समक्ष

PBR/अपील/इंदौर/भू.रा/2018/0215

इन्दौर

व्यवस्थापक, श्री चंकटेश मंदिर ट्रस्ट कमेटी,
35, छत्रीपुरा, स्ट्रीट न. 1, इन्दौर

अपीलांत

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
नजूल अधिकारी,
इन्दौर

रेस्पांडेंट

श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा अपील प्रकरण न. 163 /
11-12 को दि. 22 / 10 / 2013 को अदम पैरवी
में निरस्त करने के आदेश को अपास्त कर अपील प्रकरण
को पुनःस्थापित करने के लिए प्रस्तुत विविध मामला नम्बर
21/2013-14 में दि. 21/1/2014 को पारित आदेश
के विरुद्ध द्वितीय अपील धारा 44 उपधारा 2 खण्ड 3
म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत

महोदय,

अपीलांत की ओर से सादर निवेदन हैं कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अपीलांत को मध्यप्रदेश शासन के भू-परिमाण एवं बन्दोबस्त
विभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश अनुसार दिनांक 7 / 11 / 1977 से
कसबा इन्दौर की सर्वे क. 912/2 में 13200 वर्गफुट की नजूल भूमि
पट्टे पर प्रधान की हुई है,

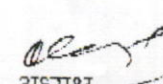
जिसके आबद रेस्पांडेंट ने धारा 182 के तहत श्रीमान
कलेक्टर महोदय, इन्दौर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलांत द्वारा
प्राप्त 13200 वर्गफुट की भूमि में से 550 वर्गफुट की भूमि पर
व्यवसायिक निर्माण कर लिया है,

जिसके आधार पर प्रकरण न. 3/अ-39/2010-11
फंजीवद कर संचालित किया जाकर उसमें श्रीमान अपर कलेक्टर
महोदय, इन्दौर द्वारा दि. 17 जनवरी 2011 को कुल लीज की भूमि में से
550 वर्गफुट की भूमि की लीज निरस्त कर उसे शासन में वेष्टित किये
जाने के आदेश पारित किये गये जिससे असंतुष्ट होकर श्रीमान अपर
आयुक्त महोदय, के समक्ष अपील प्रकरण न. 163/ 11-12 प्रस्तुत
किया था जो अपीलांत के वकील साहब की त्रुटिवश दि. 22 / 10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/भू.रा./2018/0215

प्रथम तथा दिनांक	कारण(हो) तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-1-2018	<p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21-1-2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र अवधि बाह्य प्रस्तुत किये जाने के आधार पर निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत नहीं है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर, गुण-दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायहित में प्रकरण पुर्नस्थापित कर, प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर करें ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

